

### Setting up or T.V. Station in Haryana

\*14. SHRI S.S. SURJEWALA: Will the Minister of INFORMATION & BROADCASTING be pleased to state:

(i) whether it is a fact that Haryana is the only State in the country which does not have any television station covering all the areas of the State;

(b) whether it is also a fact that no programmes in Haryanavi dialect are being prepared/telecast for the benefit of the Haryana people;

(c) whether Government are considering the setting up of a T.V. station for the exclusive coverage of programmes in Haryanavi dialect and also to cover the entire areas of the State; and

(d) whether Government also propose to start the production of Haryanavi programmes for the advancement of Haryana culture and for the benefit of its people, particularly in the rural areas?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI GIRIJA VYAS): (a) No, Sir.

(b) The Doordarshan Kendra at Delhi also telecasts programmes in the Haryanvi dialect.

(c) Subject to the approval of the competent authority, a TV Centre comprising a high power transmitter and studio is envisaged to be set up at Hissar. Programmes in Haryanvi, besides, other programmes, would be telecast from the above centre, when commissioned and the uncovered areas of Haryana are expected to be brought under TV service, in addition to improvement of service of some of the areas presently receiving fringe service.

(d) Programmes of this nature are already being telecast from DDK, Delhi and Jalandhar.

### Disparity in the earnings of pilots of Indian Airlines

\*15. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a pilot of Indian Airlines from Bombay and Madras region earns between Rs. 15,000/- and 20,000/- a month whereas a Delhi Pilot earns only between Rs. 6000/- and Rs. 8000/- a month;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) what measures Government propose to take to remove the disparity?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI MADHAVRAO SCINDIA): (a) to (c) There is no disparity in the basic wage structure of the pilots of Indian Airlines posted at any region. Difference in total earnings can be on account of variable/reimbursable allowances payable to the pilots for operation of flights. Due to different nature of operations of the flights, it is not possible to equalise the earnings of the pilots without bringing about systemic changes.

### Suggestions at the India International Aviation Congress

\*16. SHRI S. MADHAVAN: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the suggestions made in the India International Aviation Congress to improve the international airlines operations and to increase the tourist traffic;

(b) if so, what action has been taken on these suggestions; and

(c) whether the Indian citizens returning to India have to fill embarkation cards and if so, whether Government propose to scrap this procedure?

THE MINISTER OF CIVIL

AVIATION AND TOURISM (SHRI MADHAVRAO SCINDIA): (a) Yes, Sir.

(b) Only individual speakers made certain points. No recommendations were made by the Congress.

(c) There is no proposal at present to do away with the requirement of tilling up of embarkation card by the Indian citizens returning to India.

राज्य विद्युत बोर्डों को आर्थिक संकट से उबारने के लिए पावर फाइनेंस कारपोरेशन द्वारा धनराशियों का जुटाया जाना

\*17. श्री राम जेट मल्लानी:

डा० जिनेन्द्र कुमार जैन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पावर फाइनेंस कारपोरेशन ने, आर्थिक संकट का सामना कर रहे राज्य विद्युत बोर्डों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से गत कुछ वर्षों में पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा धनराशि जुटाई है;

(ख) यदि हां, तो 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के वर्षों के दौरान इन बोर्डों के माध्यम से अलग-अलग वर्षों में कितनी-कितनी राशि जुटाई गई है;

(ग) क्या यह सच है कि जुटाई गई इस राशि का उपयोग राज्य विद्युत बोर्डों को वित्तीय संकट से उबारने के लिए किया गया था;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत बोर्डों के वर्षवार कितनी-कितनी राशि दी गई थी;

(ङ) पावर फाइनेंस कारपोरेशन द्वारा गत तीन वर्षों में भारत में कार्य कर रहे विदेशी बैंकों में वर्षवार कितनी-कितनी राशि जमा कराई गई थी; और

(च) उक्त विद्युत बोर्डों को सहायता देने के बजाय बैंकों में धनराशि जमा कराने के क्या कारण थे?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाधराय):

(क) जी, हां। (ख) से (घ) वर्ष 1989-90 से 1991-92 के दौरान पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) द्वारा बांड जारी किए जाने के माध्यम से जुटाई गई राशियों और बिजली बोर्डों को संवितरित की गई राशियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(करोड़ रुपये में)

	1989-90	1990-91	1991-92	जोड़
(1) बांड के माध्यम से जुटाई गई राशि	120	620	322	1062
(2) राज्य विद्युत बोर्डों को दी गई राशि (इंफ्रस्ट्रक्चर, आंतरिक संसाधनों, विदेशी ऋण आदि सहित)	697.64	894.85	920.05	2512.54

(ङ) बांड के माध्यम से जुटाई गई राशि में से 150 करोड़ रुपये की राशि 1991-92 में एक विदेशी बैंक में जमा की गई थी क्योंकि सरकारी प्रतिभूतियों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम बांड, यूनिट्स, राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा स्थापित म्युचुअल फण्ड, वित्तीय संस्थानों एवं उनकी सहायक इकाइयों में निवेश के माध्यम से, निगम द्वारा जारी बांडों के निजी क्षेत्र में स्थापन हेतु अंशदान करने के लिए यह बैंक की पूर्व-शर्त थी।

(च) एक विकासात्मक वित्तीय संस्थान के रूप में पी एफ सी द्वारा उन सभी राज्य बिजली बोर्डों के प्रति अपनी वचनबद्धताओं को पूरा किया जाता रहा है जो पात्रता सम्बन्धी मानदण्डों को पूरा करते हैं बशर्ते अनुमोदित परियोजनाओं को निर्धारित समय-कार्यक्रम के अनुसार कार्यान्वित किया जाए। तथापि, अतिरिक्त आन्तरिक संसाधनों को जुटाए जाने के उद्देश्य से अल्पकालिक आधार पर अधिशेष निधियों को डेप्लॉय किया गया था।